नईदुनिया

त्रिपुरा में बिना लड़े जीती जंग, 345 में 77 पर कमल खिला

क्या यह लोकतंत्र की जीत है या लोकतंत्र पर सवाल ? 27 नवंबर से पहले ही खेल खत्म!

अगरतला की राजनीति में इस बार ऐसा हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ। चुनाव से पंद्रह दिन पहले ही भाजपा ने जीत का जश्न मना लिया। कारण साफ है। राज्य के पांच नगर निकायों में कुल 345 सीटों में से 77 सीटों पर भाजपा निर्विरोध जीत गई है। यानी वहां वोट डाले ही नहीं जाएंगे। या तो पर्चा भरा नहीं गया या भरा तो वापस ले लिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने जब अंतिम सूची जारी की तो विपक्ष के होश उड़ गए, क्योंकि 77 जगहों पर सिर्फ भाजपा का ही उम्मीदवार बचा था। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। यह पूरे चुनाव का करीब 22 फीसदी है। लोकतंत्र में 22 फीसदी सीटों पर बिना लड़े जीत मिल जाना अपने आप में एक बड़ा संदेश है।



ये पांच निकाय कौन से हैं, जहां यह करिश्मा हुआ है? पहला है कमालपुर नगर पंचायत, दूसरा रानीरबाजार म्युनिसिपल कार्उंसिल, तीसरा सांतिरबाजार म्युनिसिपल कार्उंसिल, चौथा सोनामुरा और पांचवां मोहनपुर नगर पंचायत। इनमें से कई जगहों पर तो ऐसा हुआ कि 65 सीटों पर किसी अन्य दल ने पर्चा ही नहीं भरा। सोचिए, लोकतंत्र में विपक्ष पर्चा भरने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। बाकी 12 सीटों पर विपक्ष ने पर्चा तो भरा, लेकिन आखिरी दिन नाम वापस ले लिया। अब सवाल है कि नाम क्यों वापस लिया गया? क्या डर से या समझौते के कारण? विपक्ष कह रहा है कि उसे डराया गया, जबकि भाजपा का कहना है कि यह संगठन की ताकत से मिली जीत है। त्रिपुरा की राजनीति को समझिए। त्रिपुरा कभी लाल गढ़ था। 35 साल तक सीपीएम ने राज किया। बुद्धदेव भट्टाचार्य से लेकर माणिक सरकार तक वामपंथ का झंडा ऊंचा रहा। फिर 2018 में भाजपा ने ऐसा झटका दिया कि लाल किला ढह गया। अब वही भाजपा नगर निकायों में भी वामपंथ को जड़ से उखाड़ रही है। कांग्रेस तो पहले ही कमजोर हो चुकी है, अब सीपीएम भी उम्मीदवार नहीं जुटा पा रही है। यह केवल चुनावी जीत नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक जीत भी है। भाजपा ने बूथ स्तर पर ऐसा जाल बिछाया है कि विपक्ष को बूथ एजेंट तक नहीं मिल रहे हैं। जब एजेंट ही नहीं होंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा?

भाजपा की रणनीति क्या है? उसकी रणनीति बहुत साफ है। पहले पन्ना प्रमुख, फिर बूथ अध्यक्ष और फिर शक्ति केंद्र। त्रिपुरा में भाजपा ने दो हजार कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है, जो घर-घर जाती है, लाभार्थियों को योजनाओं का हिसाब देती है। केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं और फिर वोट मांगती है। विपक्ष के पास न इतने कार्यकर्ता हैं और न ही ऐसी संगठनात्मक ताकत। इसलिए वह मैदान में टिक ही नहीं पा रहा है। कई जगहों पर तो विपक्षी उम्मीदवारों ने खुद ही कहा कि हमें हारने से ज्यादा हार के बाद की चिंता सता रही थी, इसलिए हमने नाम वापस ले लिया। यह डर नहीं तो और क्या है?अब बड़ा सवाल है कि क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? यदि 77 सीटों पर जनता को वोट देने का मौका ही नहीं मिला तो क्या इसे लोकतंत्र कहेंगे? विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या कह रहा है और भाजपा इसे लोकतंत्र की ताकत बता रही है। सच बीच में कहीं है। त्रिपुरा में मतदाता अब विकल्प नहीं तलाश रहा, वह सीधे सत्ता के साथ जाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि सत्ता के साथ रहेंगे तो काम होगा, सड़क बनेगी, पानी आएगा और बिजली मिलेगी। इसलिए वह विपक्ष को वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करना चाहता। यह सोच खतरनाक भी है और व्यावहारिक भी।

आगामी 27 नवंबर को बाकी 268 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन भाजपा अभी से बढ़त में है। 77 सीटों की बढ़त लेकर वह मैदान में उतरेगी और विपक्ष शून्य से शुरुआत करेगा। इस जीत का असर 2028 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। यदि नगर निकायों में भाजपा का यही प्रदर्शन रहा तो विधानसभा में भी उसका रास्ता आसान हो जाएगा। पूर्वोत्तर में भाजपा का यह मॉडल अब नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में भी अपनाया जा रहा है। पहले संगठन बनाओ, फिर सत्ता पाओ और फिर विपक्ष को मैदान में ही मत आने दो। त्रिपुरा की यह कहानी केवल त्रिपुरा की नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में भगवा लहर की नई पटकथा है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

छह हजार आठ सौ करोड़ का बजट किसके नाम ? एक चौथाई हिस्सा शिक्षकों के खाते में, बाकी बच्चों के इंतजार में...

प्रदेश में स्कूली शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए केंद्रीय स्तर पर आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में 6,810.78 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। बजट के विश्लेषण से सामने आता है कि कुल राशि का करीब एक चौथाई हिस्सा शिक्षकों के वेतन पर खर्च हो रहा है। समग्र शिक्षा के बजट में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी देखें तो शिक्षकों के वित्तीय प्रोत्साहन और वेतन पर 26.64 प्रतिशत, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर 17.87 प्रतिशत, अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर 5.53 प्रतिशत, मुफ्त पोशाक पर 3.27 प्रतिशत, आईसीटी लैब आदि पर 5.78 प्रतिशत, कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा पर 1.24 प्रतिशत तथा शिक्षक शिक्षा और लैंगिक समानता पर 5.85 प्रतिशत खर्च का प्रावधान है। ये आंकड़े केवल आंकड़े नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोध का दस्तावेज हैं। पहली बार इस स्तर पर समग्र शिक्षा के तहत प्राथमिक शिक्षा को सबसे अधिक हिस्सा देने की बात कही गई है। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्राथमिक स्कूल आज भी सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। भवन हैं तो शिक्षक नहीं, शिक्षक हैं तो छात्र नहीं और छात्र हैं तो गुणवत्ता नहीं। बजट का बड़ा हिस्सा यदि वेतन में ही चला जाएगा तो शेष राशि में भवन, प्रयोगशालाएं, किताबें, पोशाक और प्रशिक्षण जैसी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यही गंभीर सवाल इस बजट के साथ खड़ा होता है। क्या हम शिक्षा दे रहे हैं या केवल शिक्षा व्यवस्था का वेतन दे रहे हैं?

शिक्षकों के वेतन पर बड़ी राशि खर्च होना बताता है कि शिक्षा विभाग में संसाधनों का संतुलन कितना जरूरी है। इसमें दोष शिक्षकों का नहीं है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं और उन्हें पूरा वेतन मिलना ही चाहिए, लेकिन समस्या नियोजन की है। जब हम नए शिक्षकों की भर्ती करते हैं, लेकिन उनके प्रशिक्षण पर अपेक्षाकृत कम खर्च करते हैं तो

वेतन में उलझा शिक्षा का भविष्य



वेतन तो देते हैं, पर दक्षता बढ़ाने के लिए पर्याप्त निवेश नहीं करते। जब आईसीटी लैब पर सीमित राशि और कौशल शिक्षा पर केवल 1.24 प्रतिशत खर्च करते हैं तो बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने की हमारी गंभीरता पर सवाल उठता है। यह बजट का नहीं, दृष्टि का संकट है। गंभीरता से देखें तो यह बजट शिक्षा से ज्यादा व्यवस्था की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। गुणवत्ता पर 17.87 प्रतिशत खर्च का प्रावधान यह सवाल खड़ा करता है कि क्या गुणवत्ता वेतन के बाद की चीज है? जबकि सच यह है कि वेतन गुणवत्ता सुनिश्चित करने का माध्यम है, स्वयं में गुणवत्ता नहीं। यदि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आता, नई तकनीक से परिचित नहीं है और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में सफल नहीं हो पा रहा है तो वेतन पर होने वाले खर्च का अपेक्षित लाभ कैसे मिलेगा? मध्यप्रदेश के कई जिलों में शिक्षकों की कमी है तो कई जिलों में उनकी अधिकता है। अनेक स्कूलों में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन बजट में इन समस्याओं के स्थायी समाधान की स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखती। बजट हर साल आता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भरोसा हर साल घटता है।

मुफ्त पोशाक पर 3.27 प्रतिशत और आईसीटी लैब आदि पर 5.78 प्रतिशत खर्च का प्रावधान बताता है कि बच्चों की बुनियादी जरूरतों और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन कितना जरूरी है। पोशाक जरूरी है, लेकिन क्या केवल पोशाक से बच्चा स्कूल में रुकेगा? प्रयोगशालाएं जरूरी हैं, लेकिन क्या सीमित बजट से हर स्कूल में उनका प्रभावी संचालन संभव है? आज का बच्चा मोबाइल पर दुनिया देख रहा है और हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी भी कई जगह ब्लैकबोर्ड तक सीमित है। कौशल शिक्षा पर केवल 1.24 प्रतिशत खर्च करना बताता है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जबकि हर माता-पिता की चिंता यही है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चे को रोजगार मिलेगा या नहीं।

प्राथमिक शिक्षा को सबसे ज्यादा हिस्सा देने का दावा उम्मीद जगाता है, क्योंकि नींव मजबूत होगी तो पूरी इमारत मजबूत होगी। लेकिन नींव मजबूत करने के लिए केवल वेतन नहीं, भवन, प्रशिक्षित शिक्षक और तकनीक भी चाहिए। समग्र शिक्षा का मूल उद्देश्य यही था कि शिक्षा व्यवस्था के सभी पहलुओं में एक साथ सुधार हो। लेकिन जब बजट का बड़ा हिस्सा वेतन में खर्च हो और बाकी जरूरतों के लिए सीमित संसाधन बचें तो समग्र विकास कैसे होगा? सरकार को विचार करना होगा कि क्या वेतन के अलावा अन्य मदों में भी राशि बढ़ाई जा सकती है और क्या केंद्र तथा राज्य मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अलग से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। इस आलेख का उद्देश्य शिक्षकों का विरोध करना नहीं है।

शिक्षक इस व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं, लेकिन व्यवस्था को समझना होगा कि केवल वेतन देकर शिक्षा की चुनौतियां दूर नहीं की जा सकतीं। शिक्षकों को बेहतर संसाधन, प्रशिक्षण और काम करने का अनुकूल वातावरण भी देना होगा। आज शिक्षक पर काम का बोझ बहुत है। चुनाव ड्यूटी, जनगणना और मध्यान्ह भोजन जैसी जिम्मेदारियां भी उसी के हिस्से आती हैं। ऐसे में गुणवत्ता सुधार के लिए समय कहां बचेगा? इसलिए बजट में वेतन के साथ-साथ कार्यभार कम करने और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। तभी वेतन पर होने वाला खर्च सार्थक होगा। 6,810 करोड़ रुपये का बजट बड़ा है, लेकिन उसकी दिशा तय करेगी कि मध्यप्रदेश की शिक्षा किस दिशा में जाएगी। यदि हम इसी तरह वेतन और व्यवस्थागत खर्चों में उलझे रहे तो आने वाले दस वर्षों में भी गुणवत्ता की चर्चा ही करते रहेंगे। यदि वेतन के साथ-साथ गुणवत्ता, कौशल और तकनीक पर निवेश बढ़ाया तो यही बजट शिक्षा का भविष्य बदल सकता है। शिक्षा का बजट केवल वेतन का बजट नहीं, भविष्य का बजट होना चाहिए और भविष्य तभी बनेगा, जब उसका निवेश क्लासरूम में दिखाई देगा, केवल कोषागार में नहीं।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)



मूडीज की मोहर, भारत की रफ्तार पर भरोसा

वैश्विक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में...

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को लेकर अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपना अनुमान बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। मजबूत खपत, निवेश और औद्योगिक गतिविधियों से अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट 'ग्लोबल मैक्रो आउटलुक' में कहा है कि भारत ने ऊर्जा कीमतों में आई उथल-पुथल का बेहतर ढंग से सामना किया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाना केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया का भारत पर बढ़ता भरोसा भी दर्शाता है। देश में उपभोक्ता मांग मजबूत है और निवेश गतिविधियों में भी सुधार दिखाई दे रहा है। यदि निजी क्षेत्र की ओर से निवेश में लगातार वृद्धि होती है तो विनिर्माण, रोजगार और उत्पादकता को बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है।

भारत की बड़ी आबादी और बढ़ता मध्यम वर्ग खपत को बनाए हुए हैं। यह ऐसी ताकत है, जो अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया जब मंदी की आशंकाओं से जूझ रही है, तब भारत में बाजारों में मांग बनी हुई है, दुकानों में बिक्री हो रही है और कारखानों में उत्पादन जारी है। यही वह अंतर है, जो मूडीज को अपना विकास अनुमान बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाकर वैश्विक ऊर्जा संकट का प्रभाव कम किया है। सरकारी समर्थन वाली तेल विपणन कंपनियों और करों में कटौती के माध्यम से उपभोक्ताओं को कीमतों में तत्काल बढ़ोतरी से कुछ राहत दी गई है। इस रणनीति से ऊर्जा कीमतों के दबाव को सीमित रखने में मदद मिली है। भारत ने एक ओर रूस से तेल की आपूर्ति बनाए रखी, वहीं दूसरी ओर खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों में भी संतुलन कायम रखा। इससे ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली। यही संतुलन आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनाए हुए है।

हालांकि, निकट भविष्य में आर्थिक विकास के सामने कुछ जोखिम भी हैं। महंगाई का दबाव बढ़ने से घरेलू खपत प्रभावित हो सकती है। भारत में खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक की दो से छह प्रतिशत की निर्धारित सीमा के ऊपरी स्तर के आसपास है। खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से परिवारों की खर्च करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून और अल नीनो की मजबूत होती परिस्थितियां कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। इसका सीधा असर ग्रामीण मांग पर पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आय और खपत का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। ऐसे में मानसून की स्थिति अर्थव्यवस्था की आगे की गति के लिए महत्वपूर्ण रहेगी।

एक और महत्वपूर्ण पहलू औद्योगिक गतिविधियों का है। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और आयात में मजबूती उद्योगों में बढ़ती गतिविधियों का संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनियों और बैंकिंग क्षेत्र ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने पर ध्यान दिया था। अब इन क्षेत्रों में बेहतर संतुलन बनने के बाद निजी कंपनियों के पूंजीगत खर्च में तेजी आने की संभावना है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) का विस्तार आर्थिक गतिविधियों की मजबूती का संकेत दे रहा है। जीएसटी संग्रह, बिक्री और वस्तुओं की मांग में सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की गई है। यह बताता है कि अर्थव्यवस्था केवल सरकारी खर्च पर निर्भर नहीं है, बल्कि निजी खपत और निवेश भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास दर का आंकड़ा केवल अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए भी मायने रखता है। 6.5 प्रतिशत विकास दर का वास्तविक अर्थ तभी होगा, जब इससे रोजगार के अवसर बढ़ें, आय में वृद्धि हो और बाजार में आर्थिक गतिविधियां तेज हों। लेकिन यह तभी संभव है, जब विकास समावेशी हो और केवल कुछ शहरों तथा उद्योगों तक सीमित न रहे। ग्रामीण भारत को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। महंगाई और कमजोर मानसून से जुड़ी चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को कृषि, भंडारण और खाद्य आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि महंगाई का बोझ आम परिवारों पर न पड़े।

मूडीज के अनुमान से एक और बात स्पष्ट होती है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। जब अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी गति का सामना कर रही हैं, तब भारत अपेक्षाकृत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। निजी निवेश बढ़ने से विकास दर को अतिरिक्त बल मिल सकता है। यही संभावना भारत को निवेश के पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित कर रही है। विदेशी निवेशक भारत में कारखाने लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहां बड़ा बाजार, युवा आबादी और आर्थिक विकास की संभावनाएं हैं। ये सभी कारक मिलकर वह भरोसा पैदा करते हैं, जो किसी रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट से भी व्यापक है।

मूडीज ने विकास दर का अनुमान बढ़ाया है, यह निश्चित रूप से अच्छी खबर है, लेकिन असली परीक्षा जमीन पर होगी। क्या यह विकास किसान के खेत तक पहुंचेगा? क्या इससे मजदूर की मजदूरी बढ़ेगी? क्या युवा को रोजगार मिलेगा? यदि इन सवालों का जवाब सकारात्मक है तो 6.5 प्रतिशत की विकास दर केवल आंकड़ा नहीं रहेगी, बल्कि देश के हर घर की आर्थिक स्थिति में बदलाव का आधार बनेगी। भारत ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाई है। अब जरूरत है कि निजी निवेश और घरेलू खपत की इस गति को बनाए रखा जाए। तभी भारत 2027 में सात प्रतिशत से अधिक विकास दर की ओर बढ़ सकेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी चमक और मजबूत कर पाएगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

डॉ. विश्वास तिवारी

क्या डोनाल्ड ट्रंप का हारना भारत के लिए फायदेमंद होगा...?

मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का हारना मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ सबसे बड़े जनादेशों में से एक रहा है। मतदाताओं ने ट्रंप की निरूंकशता को नकार दिया है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की तेजी से बढ़ती लागत, बेमतलब के युद्ध से और दूसरे देश पर थोपे गए टैरिफ से पूरी दुनिया में आर्थिक अफरा-तफरी मचाने के खिलाफ अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को नकार दिया। ट्रंप ने हमेशा से ही शक्ति प्रदर्शन में विश्वास किया है। उनकी शैली भी टकराव वाली है और उनकी भाषा कठोर रहती है। कई बार उनका आत्मविश्वास घमंड की सीमा छूने लगता है। शांति का नोबल पाने की चाहत रखने वाले ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर जो ईरान पर हमला किया, उससे अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ और उनकी सुपरपॉवर वाली छवि को झटका लगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा झटका लगा और कच्चे तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगी। ऐसा संभवत: पहली बार ही हुआ जब अमेरिका के हथियार का जखीरा खत्म होने लगा। ईरान ने इस युद्ध में सस्ते ड्रोन से हमला किया और उसे रोकने लिए अमेरिका को कई गुना महंगी ऐंटीसेप्टर मिसाइल का उपयोग करना पड़ा था। ट्रंप का बड़बोलापन चुनाव हारने के बाद भी कम नहीं हुआ। उन्होंने बयान दिया कि अगर वो ईरान को नहीं रोकते तो आज मध्य पूर्व एशिया का नामोनिशान ही नहीं होता। उन्होंने बार-बार अमेरिका को बचाने में सक्षम अपने को एक मात्र व्यक्ति के रूप में पेश किया। जब ट्रंप ने दूसरे देशों पर बढ़ा हुआ टैरिफ लगाया तो अमेरिका में भी सामान महंगा होने लगा। किसी भी देश की विदेश नीति से अक्सर आम जनता को कोई सारोकार नहीं रहता है, लेकिन वो जनता के घरेलू बजट को प्रभावित करती है। ये चुनाव परिणाम दर्शाते है कि ट्रंप अपनी जिन नीतियों के सहारे 'मेड अमेरिका ग्रेट अगेन' का नारा देते हुए देश को महान बनाने का सपना दिखा रहे थे वो लोगों को रास नहीं आया। यहां तक की उनके कट्टर समर्थक भी उनसे नाराज हो गए। उनके कई समर्थक इसलिए भी नाराज थे, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र देशों से भी अपने संबंध बिगाड़ लिए थे। प्रवासियों के खिलाफ सख्ती बरतने और उनके देश निकाला के आदेश से भी उनका चुनावी गणित प्रभावित हुआ। इससे उनके कट्टर समर्थक तो खुश हुए, परन्तु समाज का एक हिस्सा उनसे नाराज हो गया। एशिया मूल के लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया। भारतीयों के लिए एच-1 बी वीसा फीस बढ़ाने से लगभग 65 प्रतिशत प्रवासी भारतीयों ने विपक्ष का साथ दिया। डोनाल्ड ट्रंप यह जानते है कि यह उनका अंतिम चुनाव है और उन्हें अपनी रिपब्लिकन पार्टी के भविष्य की भी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने चुनाव हारने के बाद बयान दिया कि यह उनकी नहीं बल्कि उनकी पार्टी की हार है।



ट्रंप राष्ट्रपति से पहले एक शुद्ध व्यवसायी है और राष्ट्रपति रहते हुए भी अपने वित्तीय हितों को ही प्राथमिकता दी है। ट्रंप की हार से भारत के शेयर बाजार में दीपावली आ गई। यह इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप की हार से तेल के दाम कम हो गए। इसके अलावा ईरान ने भारत सहित चार देशों के लिए हुर्मुज जल मार्ग आवागमन के लिए खोल दिया। इससे भारत में तेल और गैस की किल्लत नहीं होगी। ट्रंप की हार के बाद रुपया भी मजबूत हुआ।

ट्रंप राष्ट्रपति से पहले एक शुद्ध व्यवसायी है और राष्ट्रपति रहते हुए भी अपने वित्तीय हितों को ही प्राथमिकता दी है। ट्रंप की हार से भारत के शेयर बाजार में दीपावली आ गई। यह इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप की हार से तेल के दाम कम हो गए। इसके अलावा ईरान ने भारत सहित चार देशों के लिए हुर्मुज जल मार्ग आवागमन के लिए खोल दिया। इससे भारत में तेल और गैस की किल्लत नहीं होगी। ट्रंप की हार के बाद रुपया भी मजबूत हुआ।

मध्यावधि चुनावों में एआई कंपनियों के तेजी से बनते डेटा सेंटर एक प्रमुख मुद्दा बन गए थे। चीन से एआई क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ट्रंप इनको बढ़ावा दे रहे थे। इन सेंटरों के बनने से बिजली और पानी की अधिक खपत होती है। इसलिए अमेरिकी नागरिक इसका विरोध कर रहे थे। इस मुद्दे को डेमोक्रेटिक पार्टी ने लपक लिया। अब डेमोक्रेट का संसद के दोनों सदनों में बढ़त होने से यह माना जा रहा है कि ए आई कंपनियों के डाटा सेंटर के नियमों में सख्ती बढ़ेगी। इससे अमेरिकी एआई कंपनियों के शेयर में गिरावट आई। इससे विदेशी निवेशकों ने एआई शेयरों से पैसा निकालकर भारत के शेयर बाजारों में निवेश किया। इसलिए दूसरे देशों के बजाए भारतीय शेयर बाजार में उछाल आया। ट्रंप की हार से भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होनी है इस पर भी अब भारत अपनी शर्तों पर डील कर सकता है, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बनाए हुए थे। डेमोक्रेट ट्रंप की टैरिफ नीति के विरोधी है और एशिया में भारत की ताकत का महत्व समझते है इसलिए अधर में लटके व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं। भारत सहित कई देशों को ट्रंप की हार उनके लिए राहत की खबर दिखाई दे रही है लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। ट्रंप का स्वभाव देखते हुए यह कहना आसान नहीं है कि वो अब दबाव में आ जाएंगे। अपनी हार से चिढ़े हुए ट्रंप अपने बचे हुए कार्यकाल में और भी सुनामी लाने में सक्षम है। अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट के हावी होने से ट्रंप की मुश्किले बढ़ेगी। उन्हें महाअभियोग का सामना भी करना पड़ा सकता है। एपस्टीन की फाइल भी दोबारा खुल सकती है। उन्हें अपने फैसले को लागू करने में भी परेशानी आएगी। लेकिन वह पूरे तौर पर शक्तिहीन नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास संविधान के तहत असीमित अधिकार होते है और वह किसी भी फैसले पर अपने वीटो अधिकार से फैसला लागू करा सकते हैं। वैसे भी डेमोक्रेटिक पार्टी को इतना बहुमत नहीं है कि वह उनके वीटो अधिकार पर लगाम लगा सके। ऐसा करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, जो उन्हें नहीं मिला है।

मध्यावधि चुनाव में हारने के बाद ट्रंप भारत के साथ जल्द व्यापार समझौता कर सकते हैं क्योंकि उन्हें घरेलू राजनीति में अपनी आर्थिक और कूटनीतिक उपलब्धियां दिखाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में भारत को जल्दबाजी में समझौता करने के बजाए अपनी शर्तों पर बातचीत करने का मौका मिल सकता है। अब इन परिणामों के बाद ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीतियों और एकतरफा टैरिफ फैसलों पर संसदीय निगरानी बढ़ सकती है। अब देखने की बात ये है कि भारत के साथ ट्रंप अपने कार्यकाल में बचे हुए दो साल कैसे निभाएंगे ? क्या पूरी दुनिया हार से खीझे हुए ट्रंप को देखेगी या बदले हुए नरम रूप लिए हुए ट्रंप को।